

requirements. Since the Shalla Darpan initiative has been implemented in 1099 Kendriya Vidyalayas, what is the progress in this regard?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यह जो शाला दर्पण पोर्टल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है कि अभिभावक, बच्चा और अध्यापक एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रगति को देख सकें। उसमें बच्चे की सारी प्रगति रिपोर्ट भी होगी और बच्चा क्या कर रहा है, यह भी उसमें अंकित होगा। इससे अभिभावक घर पर ही देख सकेंगे कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है। श्रीमन्, 1,000 से भी अधिक विद्यालयों में यह शुरू किया गया है। ...*(व्यवधान)*...

SHRI MOTILAL VORA: I would like to know the progress. ...*(Interruptions)*... What is the progress? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please, please. He will give the reply. ...*(Interruptions)*...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, उसकी प्रगति अपेक्षित है। उसके संबंध में कभी-कभी जो शिकायतें आ रही हैं, वे लोड के कारण हैं, क्योंकि उस पर एक साथ बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। इस दिशा में भी अपेक्षित कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह पोर्टल बहुत अच्छा है और हम सभी विद्यालयों में इसको लागू करना चाहते हैं।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: My simple point is that you are allotting only ten seats to the Members of Parliament. There is a heavy demand in Tamil Nadu. Please consider to raise this quota, at least, in the State of Tamil Nadu. Please do it, at least, for Tamil Nadu KVS. Please do it.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के बारे में भी इनकी बहुत चिन्ता रहती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में जो नवोदय विद्यालय हैं, वे सभी जिलों में जरूर खुलें। उसके लिए जितनी धनराशि की कमी होगी, उसको सरकार देने को तैयार है, ताकि वे आगे बढ़ सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you. Now, Question No. 261.

प्रारूप नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का प्रसार

*261. **श्री हरनाथ सिंह यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में संस्कृत, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को विदेशी भाषाओं की तुलना में हेय दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या 'नई शिक्षा नीति' में कोई प्रावधान किए गए हैं ताकि सभी भारतीय भाषाओं को किसी विदेशी भाषा की तुलना में अधिक सम्मान मिले?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नहीं महोदय।

(ख) सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया में है जिसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है। डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने वाली समिति ने मंत्रालय को 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रारूप एनईपी 2019, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट और साथ ही *innovate.mygov.in* प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था, पर भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से बड़ी संख्या में सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुए हैं। प्रारूप एनईपी बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है और सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और संवर्धन की अनुशंसा करता है। वर्तमान में, मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

Promotion of Indian languages in the draft New Education Policy

†*261. SHRI HARNATH SINGH YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an increasing tendency to treat Sanskrit, Hindi and other Indian languages disdainfully compared to any foreign languages in the country; and

(b) if so, whether any provisions have been made in the New Education Policy so that all Indian languages are treated more respectfully than any foreign language?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No Sir.

(b) The Government in the process of formulating a new National Education

†Original notice of the question was received in Hindi.

Policy for which detailed consultations have been carried with various stakeholders. The Committee for the Draft National Education Policy under the Chairmanship of Dr. K. Kasturirangan submitted its report to the Ministry on 31st May 2019. The Draft NEP 2019 which was uploaded on the Ministry's website and also at *innovate.mygov.in* platform has received a large number of suggestions/comments from all stakeholders including Government of India Ministries and State Governments. The Draft NEP promotes multilingualism and recommends the equal development and promotion of all Indian languages. Currently, the Ministry is in the process of finalising the National Education Policy, 2019.

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न था कि क्या यह सच है कि देश में संस्कृत, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को विदेशी भाषाओं की तुलना में हेय दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है? माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Put your question, please.

श्री हरनाथ सिंह यादव: सर, उस पर मैं आ रहा हूँ। मान्यवर, पूज्य महात्मा गाँधी जी ने कहा था, "राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है और मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि कोई हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे या उसकी तरफ देखकर शरमाये।" इसी क्रम में संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर जी का 11 सितम्बर, 1949 को 'The Sunday Times', नई दिल्ली में एक बयान छपा था। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please ask your question. Don't read the reply.

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, उसका शीर्षक था- "Sanskrit as National Language of Indian Union."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You don't need to read that again. Put your question.

श्री हरनाथ सिंह यादव: सर, मेरा मंत्री जी से सवाल है कि पूज्य महात्मा गाँधी जी एवं डा. अम्बेडकर जी के संस्कृत, हिन्दी व समस्त भारतीय मातृभाषाओं को सम्मानित व समृद्धिशाली बनाने के सपनों की 70 साल से चल रही अब तक की हत्या को और आगे कितने दिनों तक चलाने की योजना है? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Only one supplementary will be allowed to him. This is not the way. Now, reply please.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हिन्दी और संस्कृत भाषा व अन्य भारतीय भाषाओं की अवहेलना की बात माननीय सदस्य ने बताई है, मैं इस सदन में गौरव के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आज दुनिया के लगभग 50 से भी अधिक देशों में और लगभग 250 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। श्रीमन्, अकेले जर्मनी में 44 विश्वविद्यालय संस्कृत पढ़ा रहे हैं और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत और हिन्दी की पीठ है।

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने हिन्दी से संबंधित प्रश्न भी पूछा है और उसमें इन्होंने गाँधी जी और डा. अम्बेडकर जी का उल्लेख किया है। अम्बेडकर जी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में संविधान में उल्लेख किया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Reply to the question, please.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' : जी, सर। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): A number of questions have been asked through the Chair.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' : श्रीमन्, गाँधी जी ने जो कहा था, उनकी उन अपेक्षाओं के अनुसार पूरे तरीके से हिन्दी का संरक्षण किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): He is reading out the reply and you are replying the same. Now, put your second supplementary. Put a sharp question.

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हम सभी सांसदों को दी गई नई शिक्षा नीति के 648 पृष्ठ के हिन्दी प्रारूप में 9,306 शब्द ऐसे हैं, जो विश्व के किसी भी हिन्दी शब्द-कोश में उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण हम हिन्दीभाषी अपने को अपमानित व लज्जित महसूस कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): What is your question, please? No; this is not the way.

श्री हरनाथ सिंह यादव: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी नई शिक्षा नीति के हिन्दी भाषा लिपि में अशुद्ध व त्रुटिपूर्ण छपे प्रारूप को सरल, शुद्ध व व्यावहारिक हिन्दी भाषा में पुनः मुद्रित कराने की कृपा करेंगे? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have put your question. You please sit down. Now, the hon. Minister.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, वह अभी मसौदा है। जब वह अंतिम ड्राफ्ट में आएगा, तो उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ।

SHRI K.K. RAGESH: Sir, as per the three-language formula, mother tongue must be taught in schools. But, in many Southern States, especially in Kerala, in the Kendriya Vidyalayas, mother tongue is not being taught, and, at the same time, Sanskrit has been made compulsory.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Ragesh, please put your question.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, my question is, it is a clear violation of the three-language formula. I am asking the hon. Minister whether he will intervene and ensure that the mother-tongue is taught in the KVs of Kerala and also in all other South Indian States.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण, उन्नयन, उत्थान होगा। जहां तक त्रिभाषा का सवाल है, हर हालत में प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Dr. Anbumani Ramadoss. ...**(Interruptions)**...

SHRI K.K. RAGESH: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No, nothing will go on record, Mr. Ragesh. ...**(Interruptions)**... Please sit down. No second question. Please sit down. Don't take advantage. Dr. Anbumani Ramadoss.

DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, on the New National Education Policy, the Kothari Commission way back in the 60s recommended that the total investment on education should be, at least, six per cent of the GDP. Today it is little more than just two per cent of the GDP. So, I would like to know whether the New Education Policy envisages more investment for education from the GDP.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, अभी जीडीपी का 2 प्रतिशत नहीं, बल्कि 4.34 प्रतिशत इस समय है, लेकिन हां, कोठारी कमीशन ने वर्ष 1986 में बोला था कि यह जीडीपी का 6 प्रतिशत होना चाहिए। गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति में कोशिश करेगी कि उन अनुशंसाओं का समाधान हो सके।

श्री मो. नदीमुल हक: महोदय, उर्दू एक हिन्दुस्तानी जुबान है। मेरा पूछना है कि आज जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के टीचर्स हैं, एस.सी./एस.टी. रोस्टर में होने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है। महोदय, जो नई education policy आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी उर्दू स्कूल्स टीचर्स को एस.सी./एस.टी. रोस्टर से बाहर रख कर कोई परमानेंट सॉल्यूशन तलाश करें।

† جناب محمد ندیم الحق : مہودے، اردو ایک ہندوستانی زبان ہے۔ میرا پوچھنا ہے کہ آج جو اردو میڈیم اسکولس کے ٹیچرس ہیں، ایس۔سی۔/ایس۔ٹی۔ روستر میں ہونے کی وجہ سے ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہودے، جو نئی ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ منتری جی اردو اسکولس ٹیچرس کو ایس۔سی۔/ایس۔ٹی۔ روستر سے باہر رکھ کر کوئی مستقل حل تلاش کریں۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): It is only a suggestion. That is a suggestion.

श्री रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, आज भी उर्दू के उत्थान के लिए बहुत काम किया जा रहा है। ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Ask question; don't make suggestions, please. Experienced Members are doing like this.

श्री रमेश पोखरियाल निशंक: उर्दू की परिषद् बनाकर काम किया जा रहा है, जहां तक सवाल शिक्षकों का है, उनके लिए भी काम किया जा रहा है और ज़रूरत होगी तो उनको और सशक्त करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Question No. 262. Shri Ripun Bora.

Introduction of 5G spectrum mobile broadband

*262. SHRI RIPUN BORA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government proposes to introduce 5G spectrum mobile broadband in the country;

(b) if so, whether the bidders of 4G have proven their eligibility to provide satisfactory services to the nation therein;

†Transliteration in Urdu Script.